

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :-श्री हरफूलसिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-103/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/103

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

मदनलाल पुत्र तेजाराम,
कौम भाट, निवासी- नया
गांव, तहसील पाली, जिला
पाली।

1. अलिया पुत्री ओकाराम, भाट
2. सोनाराम पुत्र ओकाराम, भाट
3. बुदाराम पुत्र ओकाराम, भाट
4. पपाराम पुत्र ओकाराम, भाट
5. सागरराम पुत्र ओकाराम, समस्त
भाट, निवासीगण भाटो का बास,
सेलडी, तहसील आहोर, जिला
जालोर।
6. जबीया पुत्री ओकाराम पत्नी
नेमाराम, भाट, निवासी हाल
रामासीया, तहसील व जिला पाली।
7. सन्तोष पुत्री ओकाराम पत्नी
मदनलाल, भाट, निवासी- हाल
डेण्डा, तहसील व जिला पाली।
8. उपतहसीलदार भाद्राजून, तहसील
आहोर, जिला जालौर

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर नामान्तरकरण अपील सं.
25/2018 अनवान ओकाराम के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय
दिनांक 29.11.2019 नामान्तरकरण सं. 499 दिनांक 22.12.2010

उपस्थिति :-

1. श्री अशोक अरोडा, श्री तरुण उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 28/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला
कलेक्टर जालोर नामान्तरकरण अपील सं. 25/2018 अनवान ओकाराम
के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय दिनांक 29.11.2019 से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।
3. बहस वकूलाय सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि -

अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध, अनाधिकार रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो किसी भी सुरत में पोषणीय नहीं है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 450 रकबा 4.43 हेक्टेयर पर अपीलार्थी अपने नाना कालू के समय से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी की माता श्रीमती शांति का जल्दी ही देहान्त हो जाने के कारण अपीलार्थी अपने नाना कालू के पास ही निवास करता था तथा कालू के देहान्त होने पर उसके अन्तिम क्रियाकर्म भी अपीलार्थी ने ही किये थे। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के नाना कालू तथा प्रत्यर्थीगण के पिता ओकाराम की संयुक्त रेकॉर्डेड खातेदारी की कृषी भूमि रही है तथा अपीलार्थी मृतक खातेदार की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र है। ऐसी स्थिति में मृतक कालूराम का एकमात्र विधिक प्रतिनिधी अपीलार्थी ही है। जिस तथ्य को गौर किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है, जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में गम्भिर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण पारित होने के 8 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसकी बखूबी जानकारी समस्त प्रत्यर्थीगण को शुरू से ही रही थी, जिस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही तथा विलम्ब को क्षमा किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां कोई अपील अथवा आवेदन विधि द्वारा समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है वहां विरोधी पक्षकार के हक में एक विशेष अधिकार का सृजन हो जाता है। जब तक विलम्ब क्षमा नहीं किया जाता तब तक न्यायालय को उक्त अपील अथवा आवेदन सुनने का क्षेत्राधिकार भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन रूप से पारित किये जाने के कारण निरस्त योग्य है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां अपील लम्बी समयावधि के पश्चात्, जो कि इस मामले में 8 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई है, वहां



6/2
28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

गुणावगुण को देखा ही नहीं जा सकता बल्कि मयाद के बिन्दु पर ही अपील निरस्त योग्य हो जाती है लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध व अनाधिकार रूप से आलोच्य नामांतरकरण को निरस्त करने में गम्भिर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने न तो पक्षकाराण के विवाद को समझा एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सकारण आदेश भी पारित किया गया है। वास्तव में नामांतरकण सं. 499 में ओकाराम के कायमुकामान का कोई इन्द्राज ही नहीं है बल्कि उक्त नामांतरकण सुगनी बेवा कालू का फौतगी नामांतरकण है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ओकाराम के कायमुकामान का उल्लेख होना मानना सर्वथा रेकॉर्ड के विरुद्ध होने का कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मयाद तथा प्रथम श्रेणी के विधिक वारीसान के सम्बन्ध में अनेक न्याय दृष्टान भी प्रस्तुत किये हैं किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका अवलोकन तक भी नहीं किया गया एवं न ही उस सम्बन्ध में लागू होने अथवा नहीं होने का कथन भी किया गया है।

नामांतरकण सं. 499 खातेदार सुगनी बेवा कालू का फौतगी नामांतरकण है तत्समय श्रीमती सुगनी का प्रथम श्रेणी का वारीस उसकी पूर्व मृत पुत्री का पुत्र अपीलार्थी के नाम भरा जाना था। इस कारण सर्वप्रथम उसकी पुत्री श्रीमती शांति के नाम पारित किया गया तथा पश्चात्तर्वी स्तर पर अपीलार्थी के नाम पारित किया जाना था किन्तु अपीलार्थी को विधिक जानकारी नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही तत्समय नहीं की गई किन्तु पश्चात्तर्वी स्तर पर नामांतरकण सं. 788 के जरिये अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में शांति का पुत्र होने के आधार पर इन्द्राज कर दिया गया किन्तु इस विधिक स्थिति को समझे बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य नहीं था कि शांति के हक में पारित नामांतरकरण एब इनइसियो वाइड हो फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ऐकाकी दृष्टी रखते हुए नामांतरकरण निरस्त कर दिया, जिस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का निष्कर्ष दिये हुए ही बिना सकारण ही आदेश पारित किया गया है जो विधिनुसार पोषणीय नहीं है। किसी व्यक्ति की धर्मजता से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवादित बिन्दुओं का समावेश हो उनका निस्तारण घोषणात्मक वाद से ही किया जा सकता है। नामांतरकण व उसकी अपील मात्र सरसरी कार्यवाही है जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकारों से बाहर जाकर अपीलार्थी को उसके हक, अधिकारों से सरसरी कार्यवाही में महरूम करने की चिष्टा की है जिस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

विधिनुसार म्युटेशन एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं होता है वहीं स्वयं अधिनस्थ न्यायालयों ने आलोच्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



निर्णय पारित कर अपीलार्थी के हक व अधिकार समाप्त ही करने का प्रयास किया है जो अधिनस्थ न्यायालय के सीमा क्षेत्र का नहीं है।

पटवारी से नामांतरकरण की जानकारी होना प्रत्यर्थागण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया गया है लेकिन पटवारी द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण सं. 499 जो कि उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा दिनांक 22. 12.2010 को पारित किया गया उसे पुनः बहाल किया जावे। अन्य अनुतोष लाभप्रद अपीलार्थी प्रदान फरमाया जावें।

6. रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने रेस्पोंडेंट अलीया व अन्य की ओर से लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि—

उक्त अपील के सदरभित म्युटेशन कमांक 499, 22/12/2010 का मृतक व्यक्ति शांति पुत्री कालु के नाम भरा गया जबकि मृतक व्यक्ति के नाम का म्युटेशन भरने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। मृतक व्यक्ति के नाम का भरा गया म्युटेशन एब-इनिशयो-वॉइड है यानि की शून्य की परिभाषा में आता है, उक्त तथ्यों की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29/11/2019 के अंतिम ऑपरेटिव भाग में पैरा संख्या 06 में लाईन संख्या 01 से 05 में वर्णित है।

श्रीमान के न्यायालय द्वारा रेवन्यु रेकॉर्ड में इन्द्राज तथ्यों की जाँच करने का ही क्षेत्राधिकार है, उत्तराधिकारीयो के संदर्भ में विवेचना करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को उपलब्ध नहीं है। उत्तराधिकार का बिन्दु तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। इस संदर्भ में इस लिखित बहस के साथ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/11/2019 की प्रतिलिपी सलग्न है।

उक्त म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन क्रमांक 788, दिनांक 30/05/2018 को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि शांति पुत्री कालुराम की मृत्यु दिनांक 02/01/1971 का होना अंकित करते हुए उक्त म्युटेशन भरा गया जब शांति की मृत्यु अपीलांट के कथनानुसार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 04/11/1975 जो हिन्दु सेवा मण्डल पाली द्वारा जारी रजिस्ट्री की कोपी से भी साबित है तथा अपीलांट मदनलाल द्वारा दिये गये अपने शपथ पत्रों में अपनी माताजी शांति का स्वर्गवास दिनांक 10/06/1976 को बताया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की माताजी शांति की मृत्यु निश्चित तौर पर अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन कमांक 788, दिनांक 30/05/2018 के भरे जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट अपने द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं अपने द्वारा प्रस्तुत अपनी माता शांति के मृत्यु प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों से बाहर नहीं जा सकता है, यह स्वीकारोक्ति तथ्य है कि अपीलांट की माताजी शांति की मृत्यु अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन कमांक 788, दिनांक 30/05/2018 के पूर्व करीबन 30 वर्षों से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी, इसके बावजूद भी रेवन्यु अधिकारीयो से मिलावट कर षडयंत्र रचकर उक्त कूटरचित फर्जी म्युटेशन के दस्तावेज निष्पादित



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किये गये जो शून्य दस्तावेज की परिभाषा में आता है जिनको खारिज किया जाना कानूनन लाजमी है। यहाँ तक की अपीलार्थी मदनलाल का जन्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात होने से इनके वारीश होने का कथन भी संदिग्ध है, उक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/11/2019 के पेज नम्बर 04 के लाईन संख्या 22 से 25 में "वैसे भी पिताजी की सम्पत्ति में पुत्री को उस समय मिलता है जब पिता की मृत्यु के समय पुत्री जिंदा हो इस प्रकरण में पिता की मृत्यु 1989 में हो गयी तथा उसकी पुत्री शांति की मृत्यु इससे पूर्व वर्ष 1971 में हो चुकी थी, दूसरे शब्दों में शांति के पिता की मृत्यु के समय शांति जीवित नहीं थी इसलिए शांति को उक्त म्यूटेशन के जरिये कोई हक नहीं मिल सकता है तथा अपीलांत मदनलाल का विधि सम्मत वारीशान होने का कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि शांति के पूर्व पति तेजाराम की मृत्यु होने के पश्चात शांति का दुसरा नाता विवाह मस्तान बाबा पाली में किया गया था तथा अपीलांत मदनलाल के नैचुरल पिता तेजाराम की मृत्यु के पश्चात अपीलांत मदनलाल का जन्म हुआ था इस परिस्थितियों में अपीलांत मदनलाल के वास्तविक पिता का नाम पूर्णतया संदेह के घेरे में है। न ही मदनलाल शांति का विधिक वारिश है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त फर्जी, कूटरचित म्यूटेशन अपीलांत मदनलाल ने षडयंत्र रचकर मात्र उक्त कृषि भूमि को हड़पने की नियति से विधि विरुद्ध अपनी मृतक माता शांति के नाम म्यूटेशन भरवाकर प्राप्त करने का षडयंत्र रचा है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं हैं जो निरस्त हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि अपीलांत मदनलाल द्वारा प्रस्तुत अपने स्वयं के पहचान बाबत दस्तावेज आधार कार्ड व वोटर कार्ड से स्पष्ट है जो लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत 2007(1) आरआरटी पेज सं. 723, 2010(2)आरआरटी पेज सं.1207, 2011(2)आरआरटी पेज सं. 1057, 2009(2)आरआरटी पेज सं. 1337 पेश किये हैं।

अपीलांत मदनलाल, कालू पुत्र गंगाराम का कतई उत्तराधिकारी नहीं है, चूंकि: अपीलांत मदनलाल की माताजी शांति की मृत्यु, शांति के पिता कालुराम जी से करीबन 15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, यानि की शांति के पिता वर्ष 1989 में हुई थी। यानि जब पुत्री का हक अधिकार ही अपने पिता की भूमि में नहीं खुल्ला तब अपीलांत मदनलाल की माताजी शांति के मृत्यु के करीबन 35 वर्ष पश्चात, मृतक शांति के म्यूटेशन के आधार पर अपीलांत का हिस्सा खोला जाना विधि विरुद्ध जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है, हालांकि उत्तराधिकार बाबत तथ्यों की विवेचना करने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है फिर भी पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्यों की विवेचना करने से यह स्पष्ट है कि उक्त षडयंत्र सुनियोजित षडयंत्र से रचकर मृतक व्यक्ति का विधि विरुद्ध म्यूटेशन भरा जाना कानूनन अपराध है, जिस हेतु विभागीय जाँच की जाकर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है। इस बाबत विधि सम्मत सम्बंधित नजीरे इस बहस के साथ पेश की जा रही है।

अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि उक्त लिखित बहस स्वीकार फरमावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवादित भूमि के मूल खातेदार कालू भाट की मृत्यु होने के उपरान्त उसकी पत्नि सुगनी



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी। सुगनी पत्नि कालू की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री शांति के पक्ष में ना.स. 499 व शांति की मृत्यु होने के उपरान्त ना.स. 788 शांति के पुत्र मदनलाल प्राथी अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये गये थे। जिनके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील मृतक कालू के भाई ओका के वारिसान द्वारा प्रस्तुत होने पर इन दोनो नामान्तरकरण को निर्णय दिनांक 29.11.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील प्रार्थी अपीलाण्ट मदनलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दोनो पक्षों के विद्वान वकीलो द्वारा प्रस्तुत बहस पर गहनता पूर्वक विचार किया गया। बाद अवलोकन पाया गया की हस्तगत द्वितीय अपील पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर की निर्णित प्रथम अपील पत्रावली में संलग्न उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.08.18 के बिन्दु सं. 5 अनुसार अपीलाण्ट मदनलाल का जन्म शांति के गर्भ से होना माना गया है। इस प्रकार मदन शांति का विधिक वारिस है, चाहे उसका जन्म किसी भी पति/पुरुष के युग्म से हुआ हो। मदन की उत्पत्ति जायज या नाजायज संतान के रूप में होने से प्राथी मदनलाल का उसकी माता से मिलने वाले विरासतन हक से वंचित नहीं रखा जा सकता है। साथ ही शांति का सुगनी की पुत्री होना भी एडमिटेड फेक्ट है। सुगनी की मृत्यु होने पर विधिक रूप से वारिस उसकी एक मात्र पुत्री शांति ही है। सुगनी की मृत्यु उपरान्त उसकी विधिक वारिस शांति के नाम नामान्तरकरण संख्या 499 दर्ज होने में विलम्ब होने पर शांति के हक हकूको पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही शांति की मृत्यु पर मदन के हक हकूको पर भी कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विरासत का नामान्तरकरण समयबद्ध विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का दायित्व राजस्व विभाग का है। एवं यह प्रक्रिया मात्र भू राजस्व अभिलेखों को अधतन रखने की प्रक्रिया मात्र (फिक्सल प्रेसिडिंग) है। इसके विलम्ब से या त्रुटिपूर्वक सम्पन्न करने से किसी के विधिक हको पर कतई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। सुगनी की मृत्यु पर विरासत का ना.स. 499 के दर्ज करने में शांति व मदनलाल के हको पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यह ना.करण सं. 499 भी अपूर्ण दर्ज किया गया था। इसी ना.करण सं. 499 के जरिये शांति की मृत्यु सहित उसके पुत्र मदनलाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करना चाहिए था जो बाद में ना.स. 788 दि. 30.5.2018 द्वारा दर्ज किया गया। यह स्थिति राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर भी एक प्रश्नचिन्ह है। साथ ही शांति की मृत्यु प्रमाण पत्र के मृत्यु के स्थान बाबत विवाद से शांति या मदन के विधिक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु स्थापित एक मात्र तथ्य यह है कि शांति की मृत्यु हो चुकी है। ओर इसका विधिक वारिस उसके गर्भ से जन्मा पुत्र मदनलाल अपीलाण्ट है। यह भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को कानून की कसौटी पर परीक्षण करने में विधिक भूल की है, जिसका पक्षकारों के हकहकूको पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।



प्रकरण में मृतक शांति के वारिस होने या नही होने की विधिक घोषणा का भी कोई प्रश्न विहित ही नही है क्योंकि संतान के जायज या नाजायज होने से उसकी मां से प्राप्त पैतृक सम्पति में विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। प्रकरणमें यह स्थापित तथ्य है कि मदनलाल शांति के गर्भ से जन्मा है, चाहे जायज हो या नाजायज संतान के रूप में। इस प्रकार मदनलाल शांति का विधिक वारिस होने से प्रकरण में विधिक वारिसान की घोषणा बाबत सिविल न्यायालय का भी प्रकरण नही बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर की अपील सं. 25/2018 अनवान ओकाराम के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय दिनांक 29.11.2019 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।



[Handwritten signature]
28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक28/10/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

[Handwritten signature]
28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)